"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगद/दुर्ग/09/2013-2015.''

## छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 312 ]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 6 जुलाई 2020 — आषाढ़ 15, शक 1942

## महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 26 जून 2020

## अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-13/2017/49/मबावि/50. — राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित संस्थाओं को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन के शर्त पर 05 वर्ष के लिए पंजीकृत करता है:-

| 豖.  | जिला    | बाल देखरेख<br>संस्था की प्रकृति | स्वैच्छिक संगठन<br>का नाम/प्रता                               | बाल गृह का पता                      |         |
|-----|---------|---------------------------------|---|-------------------------------------|---------|
| (1) | (2)     | (3)                             | (4)   | (5)                                 | (6)     |
| 1.  | दुर्ग ' | खुला आश्रय गृह<br>(बालक)        | बिलासपुर सेवा भारती बिलासपुर,<br>मां तुलजा भवानी मंदिर के पास | खुला आश्रय गृह (बालक)               | 80/DUR  |
|     |         | (બાલવા)                         | मा तुलजा मवाना मादर के पास<br>कुदुदण्ड, बिलासपुर छ. ग.        | जेल तिराहा पदमनाभपुर<br>दुर्ग छ. ग. | G/18-19 |

- 1. यह पंजीयन, आदेश जारी होने की तिथि से पाँच वर्षों के लिए वैध होगा.
- संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रितिनिधियों/सिमितियों द्वारा अनिवार्यत: किया जायेगा. संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी. संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो.
- 3. संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 तथा बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनो/वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा.

 संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एफ . केरकेट्टा, उप-सचिव.